

नैक (NAAC) द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997] क्रमांक के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

नयी शिक्षा नीति के प्रारूप के भाषा-विषयक प्रावधानों पर रचनात्मक सुझाव हेतु
हिंदी विवि में दो दिवसीय राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम का उदघाटन

नयी शिक्षा नीति शिक्षा में संपूर्ण क्रांति का दस्तावेज – प्रो. गिरीश्वर मिश्र

वर्धा, 16 जुलाई 2019: नयी शिक्षा नीति के प्रारूप के भाषा विषयक प्रावधानों पर
रचनात्मक सुझाव हेतु 16 और 17 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम के उदघाटन



समारोह में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, जाने-माने शिक्षाविद प्रो. गिरीश्वर मिश्र ने कहा कि नयी शिक्षा नीति के प्रारूप में गंभीरता से समग्रता में विषयों पर विचार किया गया है। समर्थ भारत के लिए किस प्रकार की शिक्षा दी जाए इसकी चर्चा प्रारूप में की गयी है। इस नीति से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में अनेक प्रावधान किए गये हैं। यह प्रारूप शिक्षा में संपूर्ण क्रांति का महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

विश्वविद्यालय के हिंदी शिक्षण अधिगम केंद्र की ओर से आयोजित राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन मंगलवार, 16 जुलाई को महादेवी वर्मा सभागार में कुलपति प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर प्रो. गिरीश्वर मिश्र बतौर मुख्य वक्ता बोल रहे थे। कार्यक्रम में बाबासाहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलाधिपति डॉ. प्रकाश बरतूनिया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के



सदस्य प्रो. किरन हजारिका, भाषा विद्यापीठ के अधिष्ठाता प्रो. हनुमान प्रसाद शुक्ल, साहित्य विद्यापीठ की अधिष्ठाता प्रो. प्रीति सागर प्रमुखता से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन हिंदी शिक्षण अधिगम केंद्र के संयुक्त निदेशक एवं संवाद कार्यक्रम के संयोजक प्रो. अवधेश कुमार ने किया तथा आभार कार्यकारी कुलसचिव प्रो. कृष्ण कुमार सिंह ने माना।

प्रो. गिरीश्वर मिश्र ने कहा कि शिक्षा नीति में महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर की शिक्षा पद्धति का भी उल्लेख होना जरूरी है। इस दिशा में संपूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए शिक्षा नीति को कारगर बनाया जाना चाहिए। भाषा विषय को लेकर उनका कहना था कि प्राइमरी में मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम होना चाहिए और पूरे देश के लिए एक भाषा आवश्यक होनी चाहिए। उन्होंने 6वीं से 8वीं तक की पढ़ाई के बीच संपर्क भाषा में पढ़ाई का सुझाव दिया। डॉ. प्रकाश बरतूनिया ने सुझाव दिया कि कक्षा 3 और 4 में बोलियों में शिक्षा दी जाए। इससे स्कूल छोड़ने वालों की समस्या कम होगी। शिक्षा में देशभक्ति, देश प्रेम और देश की सुरक्षा की भावना

बढ़ाने के उद्देश्य से आवश्यक प्रावधान करने चाहिए। प्रो. किरन हजारिका ने कहा कि शिक्षा नीति का प्रारूप संविधान को आधार मानकर वर्तमान परिस्थिति के साथ सुसंगत तरीके से बनाया गया है। उनका कहना था कि 10वीं तक त्रिभाषा का प्रावधान रखना चाहिए। उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदी के विकास का उल्लेख करते हुए हिंदी के लिए मानसिकता बदलने की



आवश्यकता पर बल दिया। कुलपति प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल ने अध्यक्षीय वक्तव्य में कहा कि शिक्षा नीति के प्रारूप में मूल्य शिक्षा, संस्कृति बोध आदि को शामिल किया जाना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था के पुनर्निर्धारण की दिशा में यह प्रारूप तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि भाषा को लेकर औपनिवेशिक दृष्टिकोण को बदलना आवश्यक है। इस अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रो. श्रीनिवास पाण्डेय, वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. बिनय राजाराम, भोपाल, भाषा विद्यापीठ के पूर्व प्रोफेसर उमाशंकर उपाध्याय सहित विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष एवं अध्यापक प्रमुखता से उपस्थित थे। इस दो दिवसीय राष्ट्रीय संवाद में देशभर के शिक्षाविद एवं विद्वान शामिल हुए हैं। कार्यक्रम का समापन बुधवार को होगा।